दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

SJU Govt. Registered Social Justice Union

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शुक्रवार 13 मार्च 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 163

एनपीआर से किसी को डरने की जरूरत नहीं: शाह

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राज्य सभा में स्पष्ट कर दिया है कि देश में एनपीआर बाबत कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया में पहले भी दस्तावेज नहीं मांगे गए थे और अब भी नहीं मांगेंगे। इसे लेकर बेवजह भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने एनपीआर पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करते हुए कहा कि किसी के पास जो भी सूचना होगी वो ही देने में स्वतंत्र है और जो नहीं होगी वह नहीं मांगी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी देने से मना करता है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। कुछ लोगों ने अफ्वाह फैलाई है कि जो व्यक्ति सूचना नहीं देंगे, उनके कॉलम में श्डीश् लिख दिया जाएगा। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि किसी भी केस में डी नहीं लिखा जाएगा।

केंद्रीय गृहमंत्री ने एनपीआर पर बोलते हुए कहा कि अगर अब भी किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो विपक्ष के नेता मेरे साथ बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आजाद, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वे दूसरे वरिष्ठ नेता जैसे आनंद शर्मा एवं दूसरे नेताओं को साथ लेकर मेरे पास आ जाएं। हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि केवल मैं ही वहां पर नहीं रहूंगा। एनपीआर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों को भी उस चर्चा में बुलाया जाएगा। हर बात पर बहुत ही खुलकर चर्चा होगी। देश में किसी को भी एनपीआर से डरने की आवश्यकता नहीं है।

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जारी नोटिफिकेशन में साफ कर दिया था कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के हाउस होल्ड सर्वे में 31 तरह की सूचनाएं देनी होंगी। इससे पहले 2010 में जब एनपीआर तैयार हुआ था, तो 16 सूचनाएं मांगी गई थी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार के एनपीआर में बायोमेट्रिक जानकारी नहीं ली जाएगी। साथ ही लोगों से जुटाई गई जानकारी के आधार पर कोई पहचान पत्र भी जारी नहीं होगा। पिछले कुछ समय से एनपीआर को लेकर कई तरह की भ्रामक सूचनाएं सामने आ रही थीं। जैसे, लोगों से बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी। एनपीआर 2010 में व्यक्ति का नाम, मुखिया से संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पतिध्पत्नी का नाम (यदि विवाहित), लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म का स्थान, घोषित राष्ट्रीयता, सामान्य निवासी का वर्तमान पता, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, स्थायी निवास पता, व्यवसायध्क्रियाकलाप और शैक्षिक योग्यता शामिल थी। इसके अलावा यूआईडीएआई के माध्यम से दोहराव को रोकने और आधार नंबर बनाने के उद्देश्य हेतु 05 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए ओआरजीआई को आवंटित राज्यों में तीन बायोमेट्रिक वस्तुतरू फोटो, 10 अंगुलियों की छाप और 02 आयरिस भी एकत्रित किए गए थे।

प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजा जाए तभी कांग्रेस मजबूत होगी : जगदीश शर्मा

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रियंका गांधी लगातार मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि को देखते हैं। प्रियंका गांधी के एक आह्वान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसी मनमुटाव छोड़ उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। आज जब कांग्रेस को जरूरत है एकजुट होने की तो प्रियंका गांधी ही है जो कांग्रेस को एक कर सकती हैं।

प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत बना सकती हैं। कांग्रेस के जुझारू नेता और राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं इसलिए यह जरूरी है कि राज्यसभा में भी गांधी परिवार से किसी को भेजा जाए और प्रियंका गांधी से उपयुक्त इस समय कोई नहीं है। पंडित जगदीश शर्मा ने कहा कि प्रियंका गांधी सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार को घेर सकती हैं। राहुल प्रियंका गांधी सेना सोनिया गांधी जी और राहुल जी से अनुरोध करती है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा में भेजा जाए क्योंकि प्रियंका गांधी एक ओजस्वी नेता है वह कार्यकर्ताओं के मन की बात समझती हैं और कांग्रेस को शिखर पर ले जाने की हिम्मत रखती हैं। पंडित जगदीश शर्मा ने कहा कि हर नेता अपने चक्कर में लगा हुआ है वह सत्ता के लालच में राज्यसभा में जाना चाहते हैं लेकिन आज देश को और राज्यसभा को प्रियंका गांधी की जरूरत है।

महत्वपूर्ण एवं खास

पीएफआई अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार

» शाहीन बाग प्रदर्शन में फंडिंग का आरोप

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पीएफआई के अध्यक्ष और सचिव को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष का नाम परवेज और सचिव का नाम इलियास है। आपको बता दें कि पीएफआई पर शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की फंडिंग का आरोप है। बताया जा रहा है कि इलियास शिव बिहार का रहने वाला है। स्पेशल सेल ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन और पीएफआई के संबंधों की जांच करते हुए दोनों की गिरफ्तारी की है। इन पर दिल्ली हिंसा भड़काने का भी आरोप है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीएफआई के सदस्य दानिश को गिरफ्तार किया था। उसे सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से दुष्प्रचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कहा था कि दानिश पीएफआई के काउंटर इंटेलिजेंस विंग का प्रमुख है और शहर भर में सीएए विरोधी प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।

दिल्ली हिंसा पर बनी चर्चा की सहमति

» भाजपा ने जारी किया व्हिप

नईदिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर आज चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान खुद विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। इससे पहले निचले सदन लोकसभा में भी बुधवार को इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी। ध्यान रहे कि राज्यसभा में विपक्ष ने दिल्ली हिंसा पर बुधवार को ही चर्चा कराने की मांग की थी। विपक्ष खत्म हो रहे दो अध्यादेशों पर भी चर्चा चाहता था। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा समेत तृणमूल के सांसदों ने दिल्ली हिंसा पर बुधवार को चर्चा का प्रस्ताव दिया था। हंगामे के चलते बुधवार को सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित हुई। उपसभापति हरिवंश ने अपने चैंबर में दोनों पक्षों के सदस्यों की एक बैठक बुलाई, जिसमें दोनों अध्यादेशों समेत दिल्ली हिंसा पर गुरुवार को चर्चा की सहमति बनी। तीसरी बार स्थगित होने के बाद जब सदन दोपहर 3ः 40 पर शुरू हुआ तो संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक में बनी सहमति का ऐलान किया।

रतनलाल की हत्या मामले में 7 गिरफ्तार

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश की राजधानी के पूर्वोत्तर जिले में फरवरी के अंत में भड़की हिंसा में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने अब इस मामले में सात आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में तीन गाजियाबाद के हैं. रतन लाल की हत्या मामले में सलीम मल्लिक, मुहम्मद जलालुद्दीन, मोहम्मद दानिश (सभी गाजियाबाद के), मुहम्मद सलीम खन, मुहम्मद अयूब, मुहम्मद मुश्ताक और एक अन्य आरोपी को पकड़ा गया है. फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल रहे रतन लाल उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी क्षेत्र के मौजपुर इलाके में तैनात थे. उन पर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया था. पत्थरबाजी में रतन लाल बुरी तरह से घायल हो गए थे. गंभीर अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी. मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले रतन लाल को बाद में शहीद का दर्जा दिया गया।

स्पेन की मंत्री कोरोना से हुई संक्रमित

मैड्रिड । स्पेन की समानता मंत्री आइरीन मोन्टेरो कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं और उन्हें उनके साथी और उप प्रधानमंत्री एवं राजनीतिक दल पोडेमोस के नेता पैब्लो इग्लेसियास के साथ पृथक रखा गया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है, आज सुबह, सरकार के सभी सदस्यों की जांच कराई जाएगी।

संसद ने दी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक को मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा (संशोधन) विधेयक 2020 को गुरुवार को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गयी। लोकसभा से इस विधेयक को पिछले सप्ताह शुक्रवार को ही मंजूरी मिल गयी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च सदन में पेश विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुये घर खरीददारों और छोटे एवं मझोले उद्योगों को हरसंभव संरक्षण प्रदान करने का आश्वासन दिया।

उच्च सदन में विधेयक पर लगभग डेढ़ घंटे तक चर्चा के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी । संसद के दोनों सदनों से इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बनने पर संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा । इससे पहले सीतारमण ने विधेयक को चर्चा के लिये सदन पटल पर पेश करते हुए कहा कि संबंधित अध्यादेश की अवधि गुरुवार मध्यरात्रि को समाप्त हो रही है। इसके मद्देनजर उन्होंने इस विधेयक को आज ही चर्चा कर पारित करने का सदन से अनुरोध किया। चर्चा के दौरान अधिकतकर सदस्यों ने दिवाला और शोधन संहिता (आईबीसी) में बार बार संशोधन करने पर सवाल उठाते हुये सरकार से छोटे उद्योगों के हितों का संरक्षण नहीं हो पाने पर चिंता जतायी। कांग्रेस के जयराम रमेश ने विधेयक के बारे में संसदीय समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा नजरंदाज किये जाने का जिक्र करते हुये कहा कि इससे कंपनियों के दिवाला होने का खतरा बढ़ेगा।

भाजपा ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची

नईदिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा की 55 सीटों के लिए होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गयी है। पहली लिस्ट में भाजपा ने कुल 11 नामों का ऐलान किया था, जिसमें से 9 भाजपा के और दो नाम सहयोगी दलों के लिए था। वहीं दूसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावे मध्यप्रदेश से डा सुमेर सिंह सोलंकी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा की दो सीटों में रामचंद्र झांगड़ा और दुष्यंत कुमार गौतम, हिमाचल से इंदू गोस्वामी और महाराष्ट्र से भागवत कराड को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कल की बात करें तो दो सीटों में से एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का घोषित कर दिया गया था। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए भुवनेश्वर कलिता को भाजपा ने असम से उम्मीदवार बनाया था। जबकि बिहार से विवेक ठाकुर, गुजरात से अभय भारद्वाज और रमीलाबेन बारा, मणिपुर से लिएसेंबा महाराज, महाराष्ट्र से उदयना राजे भोंसले, राजस्थान से राजेंद्र गहलोत, महाराष्ट्र से आरपीआई के रामदास आठवले और असम से बीपीएफ से बुस्वजीत डाइमरी के नाम शामिल थे।

ईरान में फंसे छात्रों से संपर्क करे केंद्र सरकार

नईदिल्ली (आरएनएस)। ईरान में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं. इन छात्रों ने वतन वापस आने के लिए मदद की गुहार लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि इन छात्रों से संपर्क किया जाए।

» दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र ने बहुत सारी सावधानियां बरती हैं, वहां फंसे भारतीयों का स्वाइप मंगवाया गया है. ईरान से 58 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है. बता दें कि तेहरान सहित पूरे ईरान में तकरीबन 3 हजार श्रद्धालु और भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इस पर जज ने पूछा कि क्या सरकार को जानकारी है कि छात्र कहां हैं? क्या भारतीय एंबेसी वहां काम कर रही है? जवाब में केंद्र ने कहा कि एंबेसी पूरी तरह काम कर रही है. एंबेसी वहां लोगों के संपर्क में है. ट्विटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं, याचिकाकर्ता ने कोर्ट के बताया कि परिजनों का कहना है कि वो ईमेल के जरिए छात्रों के संपर्क में हैं. उन्होंने बताया कि वहां भारतीय एंबेसी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है.

केंद्र ने कहा कि 26 फरवरी से ही ईरान सरकार ने एयरलाइंस बंद कर दी थी, सिर्फ एक एयरलाइंस ही चल रही है. इंडियन एयरफोर्स के एक विमान को परमिशन दी गई थी, जिसमें 58 भारतीयों को वापस लाया गया. इसमें महिला, बच्चे और पुरुष शामिल हैं. केंद्र ने ये भी बताया कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है. उन लोगों को वापस लाने से पहले पता भी करना है कि वो संक्रमित हैं या नहीं।

जज ने पूछा- आपने इन 58 लोगों की पहचान कैसे की? याचिकाकर्ता ने अपने पास मौजूद छात्रों की जानकारी और लोकेशन सरकार को उपलब्ध करवाई. इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि छात्रों के पास फ्लाइट के टिकट थे, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई. जज ने कहा कि सरकार को तय करना चाहिए कि इस तरह की स्थिति में कैसे काम करना है।

सीएए विरोधियों का पोस्टर हटाने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं

» योगी सरकार को झटका

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए होर्डिंग लगाने के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएगी, जिसमें यूपी के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के पोस्टर को हटाए। उपयुक्त पीठ अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार की चिंता समझ सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कानून नहीं, जिससे आपके होर्डिंग लगाने के निर्णय को समर्थन किया जा सके।

आपको बताते जाए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ में हुई हिंसा व तोड़फोड़ के आरोपियों के शहर में लगाए गए पोस्टर को हटाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ यूपी सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंची है।

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखते हुए कहा कि एक शख्स जो प्रदर्शन के दौरान बंदूक चलाता है और कथित तौर पर हिंसा में शामिल है। वह निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आदेश पारित करते हुए गलती हुई है।

इस पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने तुषार मेहता से पूछा कि वह अधिकार कहां है? जिसके तहत यूपी सरकार ने लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ कथित आगजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।

शीर्ष अदालत ने पाया कि यूपी सरकार ने होर्डिंग्स पर कथित आगजनी करने वालों का ब्योरा देने के लिए यह (कठोर) कदम उठाया था। अदालत ने कहा कि वह राज्य की बैचेनी को समझ सकता है लेकिन निर्णय को वापस लेने के लिए उसके पास कोई कानून नहीं है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या उसके पास ऐसे पोस्टर लगाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपकी इस कार्रवाई का समर्थन करता हो।

हवाई हमलों में 26 लड़ाकों की मौत

दमिश्क। सीरिया के पूर्वी दयर अल जोर प्रांत में बुधवार रात को किए गए हवाई हमलों में कम से कम 26 इराकी लड़ाकों की मौत हो गई। गैर सरकारी संगठन ने यह जानकारी दी है। सीरियाई आब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ये हवाई हमले अमेरिकी गठबंधन सेनाओं की ओर से किए गए हैं और इन्हें दयर अल जोर प्रांत के अल बुकामल शहर में अंजाम दिया गया था। ये सभी लड़ाके इराकी संगठन पापुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज से संबद्ध थे। इससे पहले ब्रिटेन की एक संस्था ने कहा था कि अज्ञात विमानों ने अल बुकामल शहर में कम से कम दस हवाई हमले किए थे।

बीईएल ने 174 करोड़ से अधिक अंतरिम लाभांश का किया भुगतान

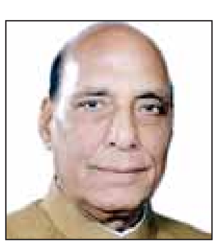

नईदिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम (डीपीएसयू), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से अंतरिम लाभांश के रूप में 174.43 करोड़ रुपये का चेक प्राप्त किया। बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एम. वी. गौतम ने रक्षा मंत्री को चेक प्रदान किया। बीईएल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने शेयरधारकों के लिए 140 प्रतिशत अंतरिम लाभांश (1.40 रुपये प्रति शेयर का एक शेयर मूल्य) घोषित किया है। यह डीपीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी से संबंधित है। बीईएल ने लगातार 16वें वर्ष अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इसने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपनी चुकता पूंजी पर 340 प्रतिशत का कुल लाभांश दिया है। भारत सरकार के पास डीपीएसयू में 51.13 प्रतिशत इक्विटी है। सचिव (रक्षा उत्पादन) राज कुमार और रक्षा मंत्रालय और डीपीएसयू के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों समेत 3 की मौत

बगदाद। इराक में हुए रॉकेट हमले में अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इराक के मिलिट्री बेस पर रॉकेट से हमला किया गया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक ब्रिटिश सैनिक की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। अमेरिका के मुताबिक बगदाद के उत्तर में ताजिया बेस पर रॉकेट दागे गए।

कॉगिंस ने ट्वीट किया कि 11 मार्च को शाम 7:35 बजे (इराक टाइम) गठबंधन (ऑपरेशन इनहेरेंट रिज़ॉल्यूशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन) 15 से अधिक छोटे रॉकेटों की पुष्टि करता है, जिसने इराक के कैंप ताजजी की गठबंधन सेना की मेजबानी को प्रभावित किया।

एक अमेरिकी सैनिक, एक ब्रिटिश सैनिक और एक अमेरिकी ठेकेदार को बुधवार को मार दिया गया, एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इराकी सैन्य बेस पर सबसे घातक रॉकेट हमले में विदेशी सैनिकों की मौत हो गई। एक युद्ध निगरानी ने कहा कि हमले से खतरनाक हमले की आशंका है, अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों ने पड़ोसी सीरिया में ईरान-गठबंधन वाले इराकी लड़ाकों को तुरंत निशाना बनाया।

बुधवार शाम को 18 रॉकेटों के एक वॉली बगदाद के उत्तर में ताजिया एयर बेस पर हमला किया गया, जो अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन से स्थानीय बलों के युद्ध जिहादियों की मदद करने वाले सैनिकों की मेजबानी करता है। गठबंधन के एक बयान में कहा गया है कि इसके तीन कर्मी मारे गए और अन्य 12 घायल हो गए, लेकिन इसने राष्ट्रीयता प्रदान नहीं की। हालांकि, एक अमेरिकी अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि मृतकों में दो अमेरिकी और एक ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं।इराकी सेना ने कहा कि रॉकेटों को एक ट्रक के पीछे से निकाल दिया गया था, लेकिन इसने किसी भी हताहत की टिप्पणी नहीं की।

इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने टेलीफोन कॉल में हमले की निंदा की।

सिंधिया आज पहुंचेंगे भोपाल, करेंगे भव्य रोड शो

नईदिल्ली (आरएनएस)। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद आज दोपहर तीन बजे भोपाल पहुंच रहे हैं। इस बाबत मध्यप्रदेश की राजधानी में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर उनका स्वागत करेंगे। राजा भोज हवाई अड्डे से भव्य रोड शो की शुरुआत कर ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा कार्यालय में आएंगे। यहां वह दीनदयाल उपाध्याय, विजयाराजे सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमाओं और माधवराव सिंधिया के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे।

अगले दिन के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, सिंधिया शुक्रवार 13 मार्च को एक बार फिर 12 बजे भाजपा कार्यालय जाएंगे। यहां से वह राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा परिसर के लिए रवाना होंगे।

गौरतलब है कि 18 सालों तक कांग्रेस में शामिल रहे सिंधिया ने बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके कुछ घंटों के भीतर ही उन्हें पार्टी से राज्यसभा का टिकट भी मिल गया था। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया को भाजपा की ओर से राज्यसभा का उम्मीदवार चुने जाने पर बधाई दी थी। सिंधिया की बगावत के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार मुश्किल में आ गई है। सिंधिया खेमे के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है।